

कृषि संज्ञा

6 अक्टूबर २०२५



ASCI
Agriculture Skill Council of India

CEASI

CENTRES OF EXCELLENCE FOR
AGRICULTURE SKILLS IN INDIA



www.ceasi.in



प्रिय पाठकों,

हमारे साप्ताहिक समाचार पत्र के माध्यम से आप तक पहुँच पाना हमारे लिए एक विशेषाधिकार है। यह समाचार पत्र CEASI की गतिविधियों की धड़कन को दर्शाता है, जो ASCI के संरक्षण में कार्यरत है, और हमारे सामूहिक सफ़र को कौशल विकास एवं सतत कृषि की दिशा में प्रतिबिंबित करता है। यहाँ साझा की जाने वाली हर कहानी हमारी टीमों, साझेदारों और कृषि समुदायों की समर्पित भावना का प्रमाण है। हमारा मिशन स्पष्ट है: किसानों और कृषि-पेशेवरों को वह कौशल, ज्ञान और तकनीक प्रदान करना जिसकी उन्हें बदलते समय में सफल होने के लिए आवश्यकता है। नवाचार और जमीनी स्तर पर जुड़ाव को मिलाकर, हम एक अधिक उत्पादक, लचीले और समावेशी कृषि क्षेत्र की नींव रख रहे हैं।

मैं आपको आमंत्रित करता हूँ कि आप इस समाचार पत्र को पढ़ें, सीखें और इसमें प्रस्तुत अवसरों में सक्रिय रूप से भाग लें। आपकी सहभागिता ही विचारों को प्रभाव में बदलती है।

डॉ. सतेंद्र सिंह आर्य मुख्य कार्यकारी अधिकारी



प्रिय पाठकों,

CEASI का साप्ताहिक समाचार पत्र केवल गतिविधियों का सारांश नहीं है। बल्कि यह एक ऐसा मंच है, जहाँ विचारों का आदान-प्रदान, उपलब्धियों का उत्सव और भारतीय कृषि तथा इसके सहायक क्षेत्रों जैसे डेयरी, बागवानी, कृषि मशीनीकरण, जलवायु लचीलापन आदि के भविष्य के लिए हमारी साझा दृष्टि को और मजबूत किया जाता है। प्रत्येक अंक कृषि क्षेत्र और विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रों से नवाचार, सहयोग और प्रगति की कहानियाँ लेकर आता है।

आगे बढ़ते हुए, हमारा ध्यान ज्ञान साझा करने, नवीनतम विकासों को सामने लाने, क्षमता निर्माण करने और सफलता की कहानियाँ हर स्तर पर किसान के खेत से लेकर नीति-निर्माताओं तक पहुँचाने पर रहेगा। ताकि आधुनिक उपकरण, तकनीकें और सर्वोत्तम प्रथाएँ उन तक पहुँच सकें जिन्हें उनकी सबसे अधिक आवश्यकता है। मैं स्वीकार करता हूँ कि यह समाचार पत्र अभी अपने प्रारंभिक चरण में है। मैं पाठकों और हितधारकों से आग्रह करता हूँ कि वे इसमें प्रस्तुत पहलों, प्रशिक्षणों और अद्यतनों से जुड़े रहें, और ऐसी प्रमुख उपलब्धियों व घटनाओं को साझा करें जिन्हें यहाँ प्रकाशित किया जा सके। इसके दायरे, प्रकाशन की आवृत्ति, नए अनुभाग जोड़ने और सुधार के लिए आपके विचार इसे एक आदर्श पत्रिका बनाने में अत्यंत महत्वपूर्ण होंगे, जो हमें साथ मिलकर और अधिक मजबूत बनने के अवसर प्रदान करेगी।

जसवंत सिंह कालसी मुख्य परिचालन अधिकारी

हम कौन हैं:

“सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर एग्रीकल्चर स्किल्स इन इंडिया (CEASI)” एक स्वायत्त संस्था है, जो “एग्रीकल्चर स्किल काउंसिल ऑफ इंडिया (ASCI)” के अधीन कार्य कर रही है। यह संस्था कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय (MSDE) के तहत कृषि और संबद्ध क्षेत्रों में कार्यरत किसानों, मजदूरी श्रमिकों, स्वरोजगार में लगे पेशेवरों, विस्तार कार्यकर्ताओं आदि के लिए कौशल विकास और क्षमता निर्माण का कार्य करती है।

CEASI कृषि के विभिन्न उप-क्षेत्रों में स्थापित उत्कृष्टता केंद्रों की शीर्ष संस्था है, जैसे कि:

- सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर डेयरी स्किल्स इन इंडिया (CEDSI)
- सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर हॉर्टिकल्चर स्किल्स इन इंडिया (CEHSI)
- सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर फार्म मेकनाइजेशन स्किल्स इन इंडिया (CEFMI)
- सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर क्लाइमेट रेज़िलिएंट एग्रीकल्चर (CoE-CRA)
- सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन एग्रीकल्चर (CoE-AI)

हम क्या करते हैं:

- **कौशल विकास और क्षमता निर्माण:** कृषि और संबद्ध क्षेत्रों में हितधारकों की आवश्यकताओं के आधार पर क्षमता निर्माण।
- **ज्ञान प्रबंधन:** वर्कफोर्स मानकों को समर्थन देने हेतु QPs, NOS, स्किल गैप रिपोर्ट और न्यूज़लेटर्स का विकास।
- **अनुसंधान:** उद्योग की मांगों के अनुसार आवश्यकताओं की पहचान और कौशल अंतर को पाटने के लिए अनुसंधान।
- **नीति समर्थन और परामर्श सेवाएं:** नवाचार साझा करने और क्षेत्रीय चुनौतियों को हल करने हेतु नेटवर्क का निर्माण।

हमारा विज़न

एक स्वायत्त उत्कृष्टता संस्थान जो कृषि में उच्च कौशल युक्त कार्यबल विकसित करने के लिए समर्पित है, नवाचार, तकनीकी प्रगति और सतत प्रथाओं के माध्यम से भारतीय कृषि की समृद्धि और लचीलापन बढ़ाने के लिए कार्यरत है।

हमारा मिशन

राष्ट्रीय और वैश्विक स्तर पर उन्नत कृषि पद्धतियों में कौशल विकास के लिए अग्रणी संगठन के रूप में उभरना, जो सततता, लाभप्रदता, क्षमता निर्माण, ज्ञान प्रसार, नीति समर्थन और नवाचार आधारित अनुसंधान के माध्यम से कृषि क्षेत्र के समग्र विकास को प्रोत्साहित करता है।

CEASI का प्रभाव:

CEASI भारतीय कृषि में एक परिवर्तनकारी बदलाव ला रहा है, जो व्यक्तियों को सशक्त बनाने, कौशल को निखारने और देशभर में समुदायों को उन्नत करने का कार्य कर रहा है।

- ▶ 15+ राज्य
- ▶ 15 एफपीओ को प्रशिक्षित और सहयोग प्रदान किया गया
- ▶ 20,000 कृषि / डेयरी पेशेवरों को कौशल प्रशिक्षण दिया गया
- ▶ 5000+ उद्यमियों को प्रशिक्षित किया गया
- ▶ 3000+ महिलाओं को सशक्त बनाया गया
- ▶ 30,000+ जीवन को प्रभावित किया गया

कृषी ओडिशा 2025-26 की तैयारी शुरू



कृषी ओडिशा 2025-26 के तीन दिवसीय कार्यक्रम की तैयारी के लिए भुवनेश्वर में एक बैठक आयोजित की गई। यह कार्यक्रम 22 से 24 जनवरी 2026 तक आयोजित किया जाएगा। बैठक की अध्यक्षता उपमुख्यमंत्री और कृषि एवं किसान सशक्तिकरण मंत्री, कनक वर्धन सिंह देव ने की, जबकि इसमें मुख्य सचिव अरविंद कुमार पाधी, कृषि निदेशक शुभम सक्सेना और मृदा संरक्षण एवं जलसंधारण निदेशक सुभ्रत कुमार पांडा समेत अन्य वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुए।

बैठक में कार्यक्रम की सुचारू रूप से आयोजन सुनिश्चित करने के लिए तैयारियों की समीक्षा और रणनीतियों पर चर्चा की गई। इस वर्ष से यह सम्मेलन जनवरी में वार्षिक रूप से

आयोजित होगा, जिससे वैज्ञानिकों, सफल किसानों, किसान उत्पादक संगठन (FPO) और कृषि उद्यमियों को अपनी सफल तकनीक और नवाचार साझा करने का अवसर मिलेगा।

2025-26 संस्करण में 250 से अधिक स्टॉल होंगे, जिनमें खेती तकनीक, महिला स्वयं सहायता समूहों और आधुनिक उपकरण प्रदर्शित होंगे। विशेष रूप से कृषि यंत्रणाओं और आधुनिक उपकरणों का प्रदर्शन किया जाएगा। आयोजन में पूरे राज्य और अन्य क्षेत्रों से 10,000 से अधिक किसान शामिल होने की संभावना है। इससे किसानों को नई तकनीकों और नवाचारों के बारे में जानकारी मिलेगी और कृषि में सुधार लाने का अवसर मिलेगा।

अंडमान और निकोबार में खेती में मशीनरी के लिए नई योजना



कृषि विभाग ने PM-RKVY की सब-मिशन (SMAM) योजना के तहत किसानों के लिए नई सब्सिडी योजना और कस्टम हायरिंग सेंटर (CHC) शुरू की है। इसका उद्देश्य छोटे और सीमांत किसानों के लिए आधुनिक कृषि मशीनरी तक पहुंच आसान बनाना है।

इस योजना में महिला और SC/ST किसान 50% सब्सिडी, जबकि अन्य किसानों को 40% सब्सिडी दी जाएगी। योजना के तहत ट्रैक्टर, पावर टिलर, सीडर, हार्वेस्टर, धान मशीन और बागवानी उपकरण उपलब्ध होंगे। साथ ही, पोस्ट-हार्वेस्ट मशीनरी जैसे ड्रायर, बॉयलर और एक्स्ट्रेक्टर भी शामिल हैं।

कस्टम हायरिंग सेंटर के जरिए किसान मशीनों को किराये पर

ले सकते हैं। इसके लिए ग्रामीण युवा, स्वयं सहायता समूह, सहकारी समितियां और FPO पात्र होंगे और 40% तक वित्तीय सहायता प्राप्त कर सकते हैं।

अधिकारियों के अनुसार, इस योजना से लागत कम होगी, उत्पादकता बढ़ेगी और सतत कृषि प्रथाओं को मजबूती मिलेगी। इससे छोटे किसानों को भी आधुनिक तकनीक का लाभ मिलेगा और कृषि के क्षेत्र में सुधार आएगा।

राष्ट्रीय शुगरकेन परामर्श: नई किस्में और छोटे किसानों के लिए मशीनरी जरूरी



देश की गन्ना अर्थव्यवस्था पर राष्ट्रीय परामर्श में किसानों, विशेषज्ञों और नीति निर्माताओं ने उत्पादन घटने, कीट और मशीनरी की कमी जैसी समस्याओं पर चर्चा की। यह कार्यक्रम रूरल वॉइस, NFCSF और ICAR के सहयोग से आयोजित हुआ।

किसानों ने उच्च लागत, कीट संक्रमण और मशीनों की कमी जैसी चुनौतियां साझा की। विशेषज्ञों ने CO-0238 की जगह नई उच्च उपज और रोग-प्रतिरोधक किस्मों के विकास की सलाह दी। साथ ही छोटे हार्वेस्टर, टिशू कल्चर सुविधाएं और AI के प्रयोग की जरूरत पर जोर दिया।

परामर्श ने इंटरक्रॉपिंग और स्मार्ट कृषि तकनीक के महत्व को

भी रेखांकित किया। सभी ने माना कि नीतियां और तकनीक भूमि स्तर पर किसानों की वास्तविक जरूरतों को ध्यान में रखकर बनाई जानी चाहिए।

इस पहल का उद्देश्य छोटे और सीमांत किसानों की आय बढ़ाना, उत्पादन सुधारना और गन्ना खेती को टिकाऊ बनाना है।

तेलंगाना में कपास और मिर्च की ड्रोन छिड़काव परियोजना



तेलंगाना सरकार कपास और मिर्च की फसलों में ड्रोन आधारित छिड़काव और निगरानी शुरू करने जा रही है। यह परियोजना कृषि विभाग, प्रो. जयशंकर तेलंगाना कृषि विश्वविद्यालय, IT विभाग और RACH के सहयोग से आयोजित होगी।

प्रारंभिक चरण में कपास और मिर्च के 25-25 एकड़ क्षेत्र पर ड्रोन का उपयोग किया जाएगा। स्टार्टअप्स AI और IoT तकनीक के साथ ड्रोन संचालित करेंगे, जिससे उच्च सटीकता के साथ छिड़काव और फसल निगरानी की जा सके। ड्रोन 6-10 एकड़ प्रति घंटे कवर करेंगे और छिड़काव की सटीकता 95% होगी।

इस पहल से किसानों की लागत कम होगी, कीटनाशक का उपयोग घटेगा और मुनाफा बढ़ेगा। स्टार्टअप्स मोबाइल ऐप और डैशबोर्ड बनाएंगे, जिससे किसान और अधिकारी स्प्रे, सिंचाई और फसल स्वास्थ्य को रियल टाइम में देख सकेंगे।

यदि परियोजना सफल रही, तो मैनुअल श्रम की जरूरत कम होगी, सिंचाई और उर्वरक प्रबंधन बेहतर होगा और सतत खेती को बढ़ावा मिलेगा। यह राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस योजना के तहत तकनीकी खेती की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है।

वैश्विक सहयोग के साथ गुजरात के उत्कृष्टता केंद्र कर रहे हैं उद्यानिकी विकास को नई दिशा



गांधीनगर: नवाचार, तकनीकी अपनाने और किसान सशक्तिकरण के माध्यम से गुजरात आधुनिक उद्यानिकी के क्षेत्र में अग्रणी राज्य के रूप में उभर रहा है। उद्यानिकी के एकीकृत विकास मिशन (MIDH) के तहत कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा देशभर में 58 उत्कृष्टता केंद्र (CoEs) स्थापित किए गए हैं, जिनमें से चार केंद्र गुजरात में संचालित हैं। ये केंद्र तकनीकी हब के रूप में कार्य करते हुए उन्नत खेती पद्धतियों, उच्च गुणवत्ता वाले पौध सामग्री और कौशल विकास को बढ़ावा दे रहे हैं। इनकी गतिविधियाँ इज़राइल, नीदरलैंड और न्यूजीलैंड जैसे देशों तथा भारतीय अनुसंधान संस्थानों के सहयोग से संचालित हो रही हैं।

साबरकांठा जिले के वद्रद में स्थित “संरक्षित खेती एवं सटीक कृषि पर उत्कृष्टता केंद्र”, जो वर्ष 2015 में स्थापित हुआ था, सतत उद्यानिकी का एक आदर्श मॉडल बन गया है। इस केंद्र ने अब तक 1.4 करोड़ से अधिक उच्च गुणवत्ता वाले सब्जियों के पौध तैयार कर वितरित किए हैं, जिनकी अंकुरण दर 90% तक रही है। साथ ही 1.13 लाख से अधिक किसानों और अधिकारियों को प्रशिक्षण, कार्यशालाओं और प्रदर्शनों के माध्यम से लाभान्वित किया गया है, जिससे अनुसंधान और क्षेत्रीय व्यवहार के बीच की खाई कम हुई है।

उद्यानिकी संस्थान उचानी में महिला सशक्तिकरण पर कृषि प्रशिक्षण प्रारंभ



करनाल: इंडो-इज़राइल परियोजना के तहत कृषि में महिला सशक्तिकरण विषय पर दो दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम उचानी स्थित उद्यानिकी प्रशिक्षण संस्थान में आयोजित किया गया। राज्य उद्यान विभाग द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में देशभर से 70 से अधिक महिला अधिकारियों ने भाग लिया, जिसका उद्देश्य कृषि क्षेत्र में महिलाओं के ज्ञान, नेतृत्व क्षमता और सहभागिता को बढ़ाना था। प्रशिक्षण सत्रों में आधुनिक खेती तकनीकों को अपनाने, प्राकृतिक संसाधनों के सतत उपयोग और कृषि में महिलाओं की सक्रिय भूमिका पर विशेष बल दिया गया।

प्रतिभागियों ने तकनीकी सत्रों के साथ-साथ घरौंडा स्थित सब्जियों के उत्कृष्टता केंद्र, लाडवा के उपोष्ण फल केंद्र और रामनगर (कुरुक्षेत्र) के एकीकृत मधुमक्खी पालन उत्कृष्टता केंद्र का दौरा किया। उन्हें संरक्षित खेती, नर्सरी प्रबंधन, आधुनिक सिंचाई प्रणाली और मूल्य संवर्धन तकनीकों का व्यावहारिक ज्ञान प्रदान किया गया। विशेषज्ञों ने लैंगिक समावेशी कृषि विकास पर अपने विचार साझा किए और बताया कि कृषि में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी भविष्य की खेती को नई दिशा दे रही है।

सेब और नाशपाती की खेती बढ़ाने के लिए हिमाचल न्यूज़ीलैंड के साथ सहयोग पर विचार कर रहा है



शिमला: हिमाचल प्रदेश सरकार सेब और नाशपाती की खेती को बढ़ावा देने के लिए न्यूज़ीलैंड के साथ सहयोग पर विचार कर रही है। इस पहल का उद्देश्य न्यूज़ीलैंड के उन्नत बागवानी अनुभव, तकनीकी हस्तांतरण और प्रशिक्षण का लाभ उठाकर उत्पादन और गुणवत्ता में सुधार करना है। चर्चा में उच्च घनत्व वाली बागवानी, कीट और रोग नियंत्रण, आधुनिक भंडारण और विपणन रणनीतियों पर ध्यान केंद्रित किया गया, ताकि हिमाचल के उत्पाद अंतरराष्ट्रीय गुणवत्ता मानकों के अनुरूप हों।

इस सहयोग से किसानों की आय बढ़ाने और राज्य की उद्यानिकी-आधारित अर्थव्यवस्था को मजबूत करने की

उम्मीद है। उन्नत और सतत खेती तकनीकों को अपनाकर हिमाचल प्रदेश प्रीमियम सेब और नाशपाती उत्पादन में वैश्विक केंद्र के रूप में स्थापित होने का प्रयास कर रहा है। प्रस्तावित सहयोग में क्षमता निर्माण और नवाचार पर जोर दिया गया है, जिससे बेहतर उत्पादन, कम नुकसान और राज्य के horticultural उत्पादों की घरेलू व अंतरराष्ट्रीय बाजार में प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता बढ़ेगी।

नारियल की खेती बढ़ाने के लिए कर्नाटक में नई योजना शुरू



मैसूरु: कर्नाटक राज्य नारियल विकास बोर्ड ने नारियल की खेती को बढ़ावा देने और मौजूदा बागानों का पुनर्जीवन करने के लिए नई योजना शुरू की है। स्थानीय उद्यानिकी विभाग के माध्यम से कार्यान्वित इस पहल का उद्देश्य इस वर्ष 1,000 हेक्टेयर अतिरिक्त नारियल बागान बढ़ाना है, जिससे वर्तमान 23,000 हेक्टेयर के क्षेत्र को और विस्तारित किया जा सके। रि-प्लांटिंग और रीजुवनेशन नारियल बागान योजना के तहत नई खेती के लिए प्रति हेक्टेयर 28,000 रुपये की सब्सिडी दी जा रही है, जो बेहतर उत्पादन, एकीकृत कृषि और नारियल उत्पादक समितियों के गठन को प्रोत्साहित करती है।

यह योजना किसानों को कीट संक्रमण और प्राकृतिक

चुनौतियों के कारण 40% तक घटे उत्पादन से उत्पन्न होने वाली नारियल और टेंडर नारियल की कीमतों में उतार-चढ़ाव से राहत देने के लिए तैयार की गई है। पायलट आधार पर, स्थानीय नारियल उत्पादक और प्रसंस्करण सहकारी समिति के सहयोग से 1,000 हेक्टेयर अतिरिक्त क्षेत्र में विस्तार कार्य शुरू किया गया है, जिससे इस वर्ष चामराजनगर तालुक में कुल 8,301 हेक्टेयर क्षेत्र में नारियल की खेती सुनिश्चित हो सकेगी। यह पहल किसानों की आय बढ़ाने और जिले में नारियल उत्पादन को सतत रूप से मजबूत करने की उम्मीद जगाती है।

₹325 करोड़ की साबर डेयरी प्लांट का रोहतक में उद्घाटन, भारत के डेयरी क्षेत्र को मिलेगा बढ़ावा



हरियाणा के इंडस्ट्रियल मॉडल टाउनशिप, रोहतक में ₹325 करोड़ की साबर डेयरी (अमूल) प्लांट का उद्घाटन किया गया। गुजरात स्थित साबरकांठा डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव मिल्क प्रोड्यूसर्स यूनियन द्वारा स्थापित यह सुविधा सहकारी डेयरी नेटवर्क को मजबूत करने और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में दूध आपूर्ति बढ़ाने का लक्ष्य रखती है।

रोहतक प्लांट अत्याधुनिक तकनीक से सुसज्जित है और इसकी दैनिक उत्पादन क्षमता 150 मीट्रिक टन दही, 3 मीट्रिक टन मट्ठा, 10 मीट्रिक टन योगर्ट और 10 मीट्रिक टन मिठाइयाँ है। हरियाणा को चुना गया क्योंकि यहाँ दूध और मट्ठे की खपत देश में सबसे अधिक है।

भारत का डेयरी क्षेत्र उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज कर चुका है, राष्ट्रीय दूध उत्पादन 2014 में 140 मिलियन टन से बढ़कर 2025 में 249 मिलियन टन हो गया है। देश दुनिया का सबसे बड़ा दूध उत्पादक बना हुआ है, जो ग्रामीण आजीविका और रोजगार सृजन में महत्वपूर्ण योगदान देता है। नई सुविधा से डेयरी मूल्य श्रृंखला में प्रसंस्करण दक्षता, गुणवत्ता और मूल्य संवर्धन को और बढ़ावा मिलने की उम्मीद है।

इंडियन इम्यूनोलॉजिकल्स ने डेयरी गायों में IBR से लड़ने के लिए भारत की पहली DIVA मार्कर वैक्सीन लॉन्च की

(Vaccine against Bovine herpes)



Indian Immunological Limited (IIL) ने Raksha-IBR लॉन्च किया, जो इंडियाज पहली देशी विकसित ग्लाइकोप्रोटीन E (gE) डिलीटेड DIVA मार्कर वैक्सीन है, और यह इंफेक्शियस बोवाइन राइनोट्रैकेटिस (IBR) से लड़ने के लिए तैयार की गई है। यह वैक्सीन नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड (NDDB) के सहयोग से विकसित की गई है और इसका उद्देश्य बांझपन, गर्भपात और दूध उत्पादन में कमी जैसी बीमारियों को नियंत्रित करना है।

IBR, जो Bovine Herpes Virus (BHV-1) के कारण होता है, भारत में प्रचलित है और यह एरोसोल और संक्रमित वीर्य के माध्यम से फैलता है। 32% से अधिक संक्रमण दर के साथ, यह

प्रतिवर्ष लगभग ₹18,000 करोड़ के आर्थिक नुकसान का कारण बनता है। नई DIVA वैक्सीन संक्रमित और वैक्सीन लगाए गए पशुओं में अंतर करने में मदद करती है, जिससे प्रभावी रोग नियंत्रण और निगरानी संभव होती है।

अनंद, गुजरात में NDDB के डायमंड जयंती समारोह के दौरान लॉन्च की गई Raksha-IBR वैक्सीन भारत के डेयरी क्षेत्र के लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है, जो पशु स्वास्थ्य, उत्पादकता और जैव-सुरक्षा को बढ़ाएगी। नियमित टीकाकरण से उच्च गुणवत्ता वाले प्रजनन पशुओं की सुरक्षा सुनिश्चित होगी और देश के डेयरी इकोसिस्टम को मजबूत किया जा सकेगा।

मुगर में ₹250 करोड़ की मदर डेयरी प्लांट का शिलान्यास, बिहार के डेयरी क्षेत्र को बढ़ावा



बिहार के डेयरी विकास में एक महत्वपूर्ण कदम के रूप में जमालपुर, मुगर में ₹250 करोड़ की मदर डेयरी प्लांट का शिलान्यास किया गया। 15 एकड़ में फैले इस प्रोजेक्ट का उद्देश्य राज्य की डेयरी अवसंरचना को मजबूत करना और 250 प्रत्यक्ष रोजगार अवसर सृजित करना है।

यह प्लांट, जो नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड (NDDB) की सहायक कंपनी है, शुरू में दैनिक 1 लाख लीटर दूध संग्रह करेगा, जिसे भविष्य में 2 लाख लीटर तक बढ़ाने की योजना है। आसपास के गांवों में स्थानीय दूध संग्रह और चिलिंग यूनिट स्थापित की जाएंगी, जिससे किसानों की भागीदारी और ग्रामीण आय में वृद्धि सुनिश्चित होगी।

डेयरी परियोजना के साथ, ₹209 करोड़ की सरसों बीज प्रसंस्करण योजनाएं भी शुरू की गईं, जो क्षेत्र में कृषि-आधारित उद्योगों को सशक्त बनाएंगी। नई मदर डेयरी सुविधा दूध संग्रह, प्रसंस्करण और मूल्य संवर्धन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी, जिससे बिहार के डेयरी क्षेत्र की समग्र वृद्धि को गति मिलेगी।

पुडुचेरी में सतत डेयरी पालन हेतु पारंपरिक पशु चिकित्सा पद्धतियों पर दो दिवसीय कार्यशाला आयोजित



पुडुचेरी स्थित ऑरोकृषि में 3 और 4 अक्टूबर को दो दिवसीय एथनो-वेटेनरी कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसका उद्देश्य पशुपालकों और डेयरी किसानों को पारंपरिक घरेलू उपचारों के माध्यम से पशुओं की देखभाल और रोग उपचार के बारे में जागरूक करना था। यह कार्यक्रम ऑरोकृषि और स्वर्णिम पुडुचेरी (श्री अरविंद सोसाइटी) द्वारा द यूनिवर्सिटी ऑफ ट्रांस-डिसिप्लिनरी हेल्थ साइंसेज एंड टेक्नोलॉजी (बेंगलुरु) के सहयोग से तथा पुडुचेरी प्रदूषण नियंत्रण समिति के पर्यावरण सूचना जागरूकता क्षमता निर्माण (EIACB) केंद्र के समर्थन से आयोजित किया गया।

बहौर क्षेत्र के 30 से अधिक डेयरी किसानों और पशुपालकों ने इसमें भाग लिया। प्रतिभागियों ने पशु देखभाल से जुड़ी वास्तविक चुनौतियों को साझा किया, जबकि विशेषज्ञों ने स्थानीय रूप से उपलब्ध जड़ी-बूटियों और प्राकृतिक सामग्री का उपयोग कर व्यावहारिक समाधान प्रस्तुत किए। कार्यशाला में पारंपरिक पशु चिकित्सा पद्धतियों को सतत, कम लागत और पर्यावरण के अनुकूल विकल्प के रूप में अपनाने पर जोर दिया गया। विशेषज्ञों ने पारंपरिक ज्ञान को आधुनिक विज्ञान से जोड़ने की आवश्यकता पर बल दिया ताकि पशु कल्याण और पर्यावरण संरक्षण दोनों सुनिश्चित किए जा सकें।

केंद्र ने पीएम धन-धान्य कृषि योजना शुरू की, 100 आकांक्षी कृषि जिलों की पहचान



केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री धन-धान्य कृषि योजना (PMDDKY) के तहत 100 आकांक्षी कृषि जिलों की पहचान की है, जो 29 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में फैले हैं। उत्तर प्रदेश ने 12 जिलों के साथ सबसे अधिक हिस्सेदारी ली है, इसके बाद महाराष्ट्र में 9, और मध्य प्रदेश तथा राजस्थान में 8-8 जिले शामिल हैं।

इस पहल का उद्देश्य कृषि उत्पादकता बढ़ाना, क्षेत्रीय संतुलित विकास को प्रोत्साहित करना और कम प्रदर्शन वाले क्षेत्रों में ऋण तक पहुँच सुधारना है। जिलों का चयन तीन मुख्य मानदंडों पर आधारित था — कम उत्पादकता, मध्यम फसल घनत्व, और औसत से कम क्रेडिट एक्सेस।

योजना को 11 विभागों की 36 योजनाओं के समन्वय के

माध्यम से लागू किया जाएगा, जिसमें कृषि एवं किसान कल्याण विभाग का योगदान सबसे अधिक (19 योजनाएं) होगा। प्रत्येक जिले के लिए समर्पित कृषि विकास योजना तैयार की जाएगी, और अनुमानित ₹24,000 करोड़ मूल्य के प्रोजेक्ट हर साल कार्यान्वित किए जाएंगे।

प्रभावी निगरानी सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने 100 केंद्रीय नोडल अधिकारियों को नियुक्त किया है, जो चयनित जिलों में PMDDKY की प्रगति और क्रियान्वयन की देखरेख करेंगे।

कैबिनेट ने 11,440 करोड़ रुपये के पल्स मिशन को मंजूरी दी



केंद्र सरकार ने पल्स उत्पादन में आत्मनिर्भरता मिशन को मंजूरी दी है। यह 2025-26 से 2030-31 तक चलने वाला छह साल का कार्यक्रम है, जिसमें कुल 11,440 करोड़ रुपये का निवेश होगा।

भारत, जो दुनिया का सबसे बड़ा दलहन उत्पादक और उपभोक्ता है, वर्तमान में 15-20% आयात करता है। मिशन का उद्देश्य उच्च उपज और रोग-प्रतिरोधी किस्मों के जरिए आत्मनिर्भरता बढ़ाना है। ICAR बीजर उत्पादन देखेगा और राज्य एजेंसियां सर्टिफाइड बीज वितरण करेंगी।

योजना के तहत 35 लाख हेक्टेयर में नई फसल बोई जाएगी और 126 लाख किंटल बीज किसानों तक पहुंचाया जाएगा।

इसके अलावा, 1,000 प्रसंस्करण और पैकेजिंग यूनिट स्थापित होंगी। सरकार तुर, उड़द और मसूर की कीमत समर्थन और खरीद सुनिश्चित करेगी।

2030-31 तक उत्पादन 350 लाख टन तक बढ़ाने का लक्ष्य है। मिशन से किसानों की आय बढ़ेगी, रोजगार सृजन होगा और टिकाऊ कृषि को बढ़ावा मिलेगा।

सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर हॉर्टिकल्चर स्किल्स इन इंडिया ने MIDH के सहयोग से हरियाणा में 3-दिवसीय किसान प्रशिक्षण शुरू किया

सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर हॉर्टिकल्चर स्किल्स इन इंडिया ने MIDH (मिशन फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर) के सहयोग से हरियाणा में प्रशिक्षण कार्यक्रम सफलतापूर्वक आयोजित किया।

पहली तीन-दिन की प्रशिक्षण कक्षा वेजिटेबल ग्रीन (सब्जी उत्पादक) जॉब रोल के लिए गाँव रामपुरा, बाबैन, जिला कुरुक्षेत्र में आयोजित की गई। इसमें 40 स्थानीय किसान शामिल हुए। प्रशिक्षण में मिट्टी की तैयारी, फसल का चयन, कीट प्रबंधन, सिंचाई तकनीक और उपज के बाद की देखभाल जैसी विषयों पर ध्यान दिया गया। इंटरैक्टिव डेमोंस्ट्रेशन और खेत आधारित गतिविधियों के माध्यम से सतत खेती, संसाधनों का सही उपयोग और बाजार-उन्मुख

उत्पादन रणनीतियों पर जोर दिया गया। प्रशिक्षकों ने छोटे और सीमांत किसानों के लिए उपलब्ध सरकारी योजनाओं की जानकारी भी दी।

इसके बाद, दूसरी बैच का प्रशिक्षण मास्टर गार्डनर जॉब रोल के लिए सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। इसमें पंचकुला नगर निगम, हॉर्टिकल्चर विभाग और वॉचलेंस विभाग के 40 प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया और तीन दिनों के प्रशिक्षण में व्यावहारिक कौशल प्राप्त किए।

इन पहलों के माध्यम से सेंटर ऑफ एक्सीलेंस किसानों और विभागीय कर्मियों को व्यावहारिक ज्ञान, नई तकनीक और कौशल प्रदान करके हरियाणा में खेती की उत्पादकता, सततता और लाभप्रदता बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है।



सश्वत मिथास पहल के तहत अयोध्या में जलवायु-अनुकूल गन्ना खेती को सुदृढ़ करना

सश्वत मिथास पहल के तहत सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस फॉर एग्रीकल्चर स्किल्स इन इंडिया(CEASI) और यूपीएल एसएस लिमिटेड साझेदारी में अयोध्या में जलवायु-स्मार्ट और टिकाऊ गन्ना को बढ़ावा दिया जा रहा है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत अब तक 90 अनऑर्गेनाइज्ड और 3 ऑर्गेनाइज्ड किसान समूहों के 500 किसानों का सर्वे किया गया, ताकि वर्तमान खेती के तरीकों को समझा जा सके और सुधार के अवसर पहचाने जा सकें। इन निष्कर्षों के आधार पर गाँव स्तर पर प्रदर्शन प्लॉट बनाए गए हैं जहाँ पानी की बचत, मिट्टी के स्वास्थ्य की देखभाल और जैविक इनपुट के उपयोग जैसी सर्वोत्तम प्रथाएँ दिखाई जा रही हैं। समुदाय की भागीदारी और सहकर्म-से-सेखने को मजबूत करने के लिए पहल ने 97 रिटेलर विज़िट, 9 फील्ड डेज़, 4

ऑर्गेनाइज्ड मीटिंग और 94 अनऑर्गेनाइज्ड मीटिंग्स आयोजित कीं, जिससे किसान विशेषज्ञों से सीधे मिल सकें, खेतों की समस्याओं पर चर्चा कर सकें और क्लाइमेट-रेज़िलिएंट तरीकों के व्यावहारिक प्रदर्शन देख सकें। फील्ड रिसर्च, लाइव डेमो और सभी हितधारकों की भागीदारी के माध्यम से यह पहल गन्ना किसानों को पर्यावरण-अनुकूल और संसाधन-कुशल तकनीकें देता है जो उपज बढ़ाती हैं, प्राकृतिक संसाधनों की रक्षा करती हैं और जलवायु परिवर्तन के खिलाफ लचीलापन बनाती हैं। इसका उद्देश्य केवल उत्पादकता बढ़ाना ही नहीं, बल्कि अयोध्या क्षेत्र में एक नकल योग्य टिकाऊ और समावेशी कृषि मॉडल स्थापित करना भी है।





CEASI

CENTRES OF EXCELLENCE FOR
AGRICULTURE SKILLS IN INDIA



(CEASI), Unit No. 101, First Floor, Greenwoods
Plaza, Block 'B' Greenwoods City, Sector-45,
Gurugram, Haryana-122009



+91 74287 06078



info@cedsi.in



www.ceasi.in



@ceasi_india